Available online at http://www.nrjp.co.in

Journal of Management Science, Operations & Strategies, (E- ISSN 2456-9305)
Vol. 5, Issue, 01.56-62p, June, 2021

National Research & Journal Publication

Review Article

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं संभावित चुनौतियाँ : एक मूल्यांकन

अंजना कुमारी
एम0 एड0, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

Abstract

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत 70 वर्षों में आजादी के बाद देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना, महाविद्यालयों में 80 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 80 गुना और शिक्षकों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है। विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाता है और एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बनियादी सुविधाओं के बिना भी हजारों कॉलेज चल रहे हैं, जहां केवल कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की ही व्यवस्था है। देश में इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेज भले ही बढ़ रहे हों, उनकी न तो गुणवत्ता बढ़ रही है, और न ही इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनका पाठ्यक्रम अपग्रेड हो रहा है। निजी महाविद्यालय कागज पर खोल तो दिए गए हैं लेकिन अनियमितताएं व्यापक है तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। यह सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट, शिक्षकों की योग्यता एवं संख्या से संबंधित है। हालत यह है कि मोटी फीस देकर एमबीए या इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर रहे लाखों युवा हर साल बेरोजगारों की कतार में शामिल हो रहे हैं, या जीविकोपार्जन की मजबूरी में अत्यंत साधारण नौकरी ज्वाइन कर अर्ध बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में बहुत से ग्रेजुएट्स के पास न तो अपने विषय की जानकारी है, न कौशल है और न ही आत्मविश्वास है। ऐसे में यहां स्किल इंडिया कार्यक्रम मददगार हो सकता है, जिसके तहत जिस विद्यार्थी को किसी खास कौशल में रुचि हो, तो वह उसे आगे बढ़ा सके और आत्मनिर्भर हो सके। भारत की कोई भी शिक्षण संस्था आज दुनिया की शीर्ष 200 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में नहीं है। जबकि पूर्वी एशिया के छोटे–छोटे देशों की कई शिक्षण संस्थाएं शीर्ष 50 की सूची में शामिल हैं। देश में लगभग चालीस हजार महाविद्यालय और आठ सौ विश्वविद्यालय हैं। सरकार वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी को 24.5 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है। हालांकि तब भी यह कम होगा, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रतिशत 80 से ऊपर है। चीन में भी उच्च शिक्षा का औसत 35 प्रतिशत से अधिक है। जहां तक आर्थिक लाभ और सुविधा की बात है, भारत की स्थिति कई यूरोपीय देशों से बेहतर है। फिर भी उच्च शिक्षा का ढांचा मजूबत क्यों नहीं बन पा रहा है? डिजिटल होने और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना संजो रहे भारत में उच्च, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा है। देश और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा नीतियों में जल्द बुनियादी बदलाव कर इन्हें अमलीजामा पहनाया जाए ताकि देश के शैक्षणिक विकास का इतिहास गौरवशाली बना रहे।

मुख्य शब्द :– *उच्च शिक्षा, शिक्षण संस्थाएँ, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम, बेरोजगारी।*

Copyright©2021 अंजना कुमारी *This is an open access article for the issue release and distributed under the NRJP Journals License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

प्रस्तावना

आजकल वैश्विक अर्थव्यवस्था, धन उत्पत्ति विकास और संपन्नता की संचालक शक्ति सिर्फ शिक्षा को ही माना गया है। शिक्षा मनुष्य को उदार चरित्रवान, विद्वान और विचारवान बनाने के साथ–साथ उसमें नैतिकता, समाज और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था की भावना का संचार करती है। किसी भी शिक्षण संस्थान के मुख्यतः तीन अंग होते हैं– शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम।

किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता इन्हीं पर निर्भर होती हैं। भारत की मानव संसाधन क्षमता को पूर्ण रूप से समानता और समावेशिता के साथ उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में लगाना मुख्य उद्देश्य है। आज विकसित राष्ट्रों के आर्थिक और तकनीकी विकास के पीछे उनके शोध का मजबूत आधार देखा जा सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले सात दशकों में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वतंत्रता पूर्व देश में मात्र तीस विश्वविद्यालय थे, वहीं अब उनकी संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। महाविद्यालयों की संख्या 500 से करीब 40,000 और विद्यार्थियों की संख्या 3,97,000 से करीब 350,00,000 के पार पहुंच गयी है। यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रत्येक वर्ष तैयार करती जा रही है। हमारे इन उच्च संस्थानों के छात्र देश, समाज और उनकी समस्याओं से कटे हुए हैं। उच्च शिक्षा की व्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है शिक्षा का सही उपयोग हम अपने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कर सकें। आज स्थिति यह है कि सिर्फ वही माता पिता अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज भेज पाते हैं जो आर्थिक रुप से सक्षम हैं। गरीबी से ज्यादा बड़ा कारण गुणात्मकता का मुद्दा है। भारत की समस्या केवल उच्च शिक्षा का कम आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसकी गुणात्मकता और एकरूपता का भी है। देश के उच्च शिक्षा संस्थान जिस तरह डिग्रियां दे रहे हैं, उनमें कई विसंगतियां हैं। अधिकांश महाविद्यालयों में सुनियोजित शिक्षण व्यवस्था का अभाव है। अनेक कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। असल में कमजोर और बेतरतीब स्कूल व्यवस्था ही उच्च शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का मुख्य कारण है। यद्यपि केंद्र सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (GER) का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी संख्या में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की जरूरत होगी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowlwdge Commission) ने 2020 तक 30 प्रतिशत लोगों को विश्वविद्यालय तक लाने के लिए अगले 10 वर्ष में देश में 1500 विश्वविद्यालय और करीब 45 हजार कॉलेज खोलने की सिफारिश की है। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति माननीय प्रणव मुखर्जी ने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि– ''हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहां युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले। उन्होंने छात्रों में आत्मचेतना, संवेदनशीलता, मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावशाली संवाद, समस्या समाधान व अंतर्वैयक्तिक संबंध की दक्षता बढ़ाने की जरूरत हैं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा तभी उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर हो पाएगी। पाठ्यक्रम की योजना, पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अलग–अलग कार्य होते हुए भी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक के भी गतिहीन होने से पाठ्यक्रम का निर्धारित उद्देश्य समग्रता में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के निजी और सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्रों में आमूल–चूल परिवर्तन जरुरी है तथा इसमें व्याप्त विमगतियों को दूर कर दोनों क्षेत्रों को एक–दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर संचालित किये जाने की जरुरत है।

भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां

उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के–स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाए है, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही हैं। योजनाएं बनाना और उनका पालन करवाना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सरकार का काम हैं परन्तु सरकार अपने

दायित्व का निर्वाह करने में निरंतर विफल रही है। हमारे शिक्षण संस्थानों के सामने भी कई तरह की सामरिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। विश्व के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत न केवल विकसित राष्ट्रों से काफी पीछे है, बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी इस दृष्टि से भारत से आगे हैं। भारत के पास जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षण संस्थानों की काफी कमी है और साथ ही इनमें शिक्षकों एवं आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। इसलिए आज भी यह सकल नामांकन अनुपात के अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। एक तरफ कक्षा में क्षमता से अधिक संख्या, प्रयोगशालाओं की कमी, लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में चालीस प्रतिशत शिक्षकों की कमी और ऊपर से रोज–रोज बढ़ते राजनीतिक दबाव आदि ।

संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमरीका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि देश के अधिकांश प्रदेशों की राज्य सरकारों की उच्च शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं है और वे इसका वित्तीय भार नहीं उठाना चाह रही है। इसी कारण अनेक प्रदेशों में यू.जी.सी. से स्वीकृत पदों को राज्य सरकार की सहमति नहीं मिली और वे समाप्त हो गए। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के पद भरे नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह अंशकालिक अध्यापकों, शोध–छात्रों या अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। देश की बढ़ती जनसंख्या और उसमें युवा वर्ग के अनुपात को देखते हुए अगले 10–12 साल में उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिनके लिए हमारे पास आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संसाधनों की स्पष्ट और सार्थक योजना नहीं है। प्रवेश परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक कामयाबी के लिए सोच–विचार कम और रटना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

कुछ अच्छे विश्वविद्यालय जैसे कि जेएनयू या दिल्ली विश्वविद्यालय निश्चित रुप से सफल हैं। क्योंकि वहां विविधता के महत्व को समझा गया है, ताकि सृजनशीलता और नवीन प्रवर्तन पनप सके। बहुत से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के फैकल्टी संयोजन और छात्र निकाय में भारत की असाधारण विविधता झलकती है। इससे भी अच्छी बात तो यह है कि उनका एक बहुत ही अलग प्रकार का पाठ्यक्रम और पाठयचर्या है, जिससे उनके शैक्षणिक विकास में वृद्धि होती है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उच्च द्य संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। एक तो समूचे देश के अंदर छात्र–शिक्षक अनुपात इतना असंतुलित है कि सोचकर ही स्थिति भयावह लगती है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। अगर हम भारत के चुनिन्दा आई. आई. टी. व विश्वविद्यालयों को छोड़ दे जो अपनी योग्यताओं के कारण विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इन संस्थानों के प्रतिभाशाली छात्र अपना देश छोड़ कर विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। दूसरी विकट स्थिति यह ऋऋऋ है कि भारतीय जनसंचार संस्थान सहित देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में तदर्थ व्यवस्था के तहत शिक्षकों की बहाली कर उनसे काम चलाया जा रहा है। कई राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं, जहाँ कई कॉलेजों में कई विभागों में एक भी शिक्षक नहीं है। देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों मे। शिक्षकों के चालीस फीसदी पद खाली हैं, तो वहाँ शैक्षणिक गतिविधियों और उनकी गुणवत्ता की क्या स्थिति होगी। यह केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति है अगर इसमें राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को भी जोड़ दिया जाए तो तस्वीर बहुत भयावह होगी। नैसकॉम और

मैकिन्से के ताजा शोध के अनुसार मानविकी में 10 में एक और अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। अभी एसोचौम (ASSOCHAM) का ताजा सर्वे बता रहा है कि देश के शीर्ष 20 प्रबंधन संस्थानों को छोड़ कर अन्य हजारों संस्थानों से निकले केवल सात प्रतिशत छात्र ही नौकरी देने के काबिल पाये गये हैं। इससे पहले जनवरी, 2016 में आयी एस्पाइरिंग माइंड्स की नेशनल इम्प्लायबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के 20 फीसदी इंजीनियरिंग स्नातक ही नौकरी देने के काबिल हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि इस देश के 90 फीसदी कॉलेजों एवं 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। कई विश्वविद्यालयों में पिछले कई सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पुराना पाठ्यक्रम और जमीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी हैं। यह निराशावादी माहौल उच्च शिक्षा केन्द्रों को विश्वस्तरीय स्थान दिलाने में असफल हो रहा हैं और उच्च शिक्षा केवल अर्ध शिक्षित बेरोजगारों की 'फौज खड़ी कर रही है।

उच्च शिक्षा के तीन निर्धारित उद्देश्य हैं शिक्षण, शोध एवं विस्तार कार्य और इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम पाठ्यक्रम होता है। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कोठारी आयोग, प्रो. यशपाल कमेटी आदि का गठन हुआ और रिपोर्ट (Reports) भी आयी। इसके आधार पर 1986 में रोजगारोन्मुखी नयी शिक्षा नीति भी लायी गयी, परन्तु आज भी हम एक अदद मूल्यपरक शिक्षा नीति की बाट देख रहे हैं। हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति देने वाला जो बिल आया है उससे गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने में निश्चित रूप से आसानी होगी, परंतु इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायतत्ता देनी होगी। वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (एनसीएचईआर) एक अच्छा प्रयास है, परंतु डर यही है कि यह भी कहीं नौकरशाही संस्कृति में फँसकर न रह जाए, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब तक आड़े आती रही है। प्रो. यशपाल का मानना है कि ''जिन शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो न तो शिक्षा का भला कर पाते हैं और न समाज का। अकादमिक प्रदर्शन सूची (एपीआई) के लागू होने के बाद प्राध्यापकों की पदोन्नति में एपीआई की गणना हो रही है और इसके चलते आजकल शिक्षा संस्थानों में हम शोध, संगोष्ठी और प्रकाशन की तत्वहीन मारामारी का अद्भुत नजारा देखने को बाध्य हो रहे हैं। गुणहीन शोध पत्रिकाओं की भीड़ लग रही है। शोध–प्रकाशन पर अतिरिक्त बल देने का खमियाजा यह है कि गली–गली से शोध की पत्रिकाएं छप रही हैं और पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन पर अधिक समय देने के कारण निश्चय ही कक्षा–शिक्षण भी प्रभावित हुआ है। इस क्रम में यूजीसी द्वारा प्रेषित शोध–पत्रिकाओं की सूची भी अवैज्ञानिक एवं अधूरी–सी है। शोध में नकल और चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दौर में महँगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड वि.वि. और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा का पनपना आज की अहम उच्च शैक्षिक चुनौतियाँ हैं।

आज शोध का भारतीय संदर्भ जटिल होता जा रहा है और उसकी उपादेयता और गुणवत्ता को लेकर उच्च शिक्षा के लाभार्थियों में काफी असंतोष सा व्याप्त होता दिख रहा है। शोध कार्यो में दोहराव एक बड़ी समस्या बन गई है और अन्य कारणों से शोध में नकल और चोरी जैसा हीन काम भी होने लगा है। वैज्ञानिक शोधों पर सरकार अभी जितना खर्च कर रही है वह हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इंफोसिस (Infosy) के संस्थापक नारायण मूर्ति ध्यान दिलाते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमरीका ने

सेमी–कंडक्टर, सूचना तकनीकी और बायोटेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है। इस सबके पीछे वहाँ के विश्वविद्यालयों में किए गए शोध कार्य का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमरीका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से सिर्फ तीन फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। भारत में भी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई जतन किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी देश में हो रहे शोध की न केवल मात्र, बल्कि उसकी गुणवत्ता को लेकर हम अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित ताजा–ताजा पेपर लीक प्रकरण चर्चित रहा है। जिसके तहत एसओजी ने विशेष कार्यवाही में विश्वविद्यालय के शिक्षक, गोपनीय शाखा के कर्मचारी, कोचिंग संचालक, पास बुक एवं पुस्तक प्रकाशकों की मिलीभगत उजागर हो रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माफिया पैदा हो गए हैं जो कि नैतिकता को तो ताक पर रखकर चलते हैं। शिक्षकों, कर्मचारियों, निजी संचालकों एवं प्रकाशकों का ऐसा गठबंधन है जो कि पैसा कमाने के चक्कर में डिग्री की विश्वसनीयता व परीक्षाओं की गोपनीयता को भंग कर रहा है, जिससे एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत और उसकी बढ़ती व्यावसायिक गिरफ्त को देखने से यही लगता है कि प्रचलित शिक्षा अधूरी, दोषपूर्ण और अपर्याप्त है। इसलिए सही अर्थों में व्यक्तित्व और कुशलता की वृद्धि की दृष्टि से अव्यावहारिक है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव :–

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। आजकल देश में उच्च शिक्षा की कमियों को दूर कर उसमें गुणवत्ता लाने की चर्चा बड़े जोरों पर है। इसके लिए अनेक स्तरों पर तरह–तरह के उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

1. आज के समय विभिन्न सामरिक और सामाजिक चुनौतियों के उन्मूलन में विज्ञान की प्रभावी भूमिका है। उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यावसायिकता की अपेक्षा गुणात्मकता, प्रतिस्पर्धा, समर्पण को महत्व दिया जाना चाहिए।

2. भारत में वैज्ञानिक शोधों पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। वैज्ञानिक शोधों पर होने वाला खर्च एक तरह से निवेश है, जिससे हमें कई तरह के प्रतिफल मिलते हैं।

3. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के प्रमुख नंदन नीलकेणी के अनुसार, ”भारत को अपने डेमोग्राफिक लाभांश का फायदा उठाना चाहिए। इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इनमें से 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच की है। यदि इन्हें ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाये तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं।’

4. किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती हैं। हमें इन कड़ियों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तभी शिक्षा व्यवस्था मे व्यापक बदलाव आ पाएगा।

5. इस योजना के अंतर्गत उन सरकारी कॉलेजों को अतिरिक्त धन एवं सुविधाएं दी जाती हैं जहां प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है तथा जहां

प्रोफेसर ठेके पर रखे गए हैं। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्रोफेसरों का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाए।

6. हर वर्ष लाखों की संख्या में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारक निकलते हैं लेकिन रोजगार परकता मात्र 10 प्रतिशत है। आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षित युवाओं की दिशा को सही जगह पर ले जाया जाए, उन्हें रोजगार परक बनाया जाना जरुरी है।

7. शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्वायत्तता को बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बड़ा कार्य संभव है। विश्वविद्यालयों के बोझिल वातावरण का निस्तारण कर उसे सुरुचिपूर्ण, हल्का तथा विचार प्रधान बनाना चाहिए। परिसर में बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार के पीछे आत्मीय संबंधों का अभाव है। यदि यहां पर एक पारिवारिक वातावरण विकसित किया जा सके तो अनेक अप्रिय प्रसंग घटित ही नहीं होंगे।

8. उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी, चुस्त, गतिशील, लचीली और अधिक विभिन्नताओं सहित होनी चाहिए। अतः शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए और शिक्षकों के लिए सतत् प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाया जाए।

9. भारत युवाओं का देश है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अहम योजनाओं को सफल बनाना है तो इसके लिए युवाओं को सही राह दिखानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा दी जाए।

10. हमारी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये और प्रोफेसरों की पदोन्नति को ऑनलाइन कोर्स बनाने से जोड़ दिया जाए। चॉक और ब्लैक बोर्ड के जमाने को भुला कर शिक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

11. स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाए। कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले शिक्षण सस्थानों के संचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतन्त्रता दी जाए।

12. कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को इनउ च्च शिक्षण संस्थानों मे शुल्कों में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन संस्थानों मे प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।

13. सरकार को समय–समय पर अपनी लागू योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर उनमें बदलाव करने की भी जरूरत है। शिक्षकों के व्यावसायिक उत्थान के लिए लागू किये गये कार्यक्रम जैसे ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेसर कोर्स आदि की समीक्षा भी जरूरी है। सस्थानो द्वारा सचालित पाठ् यक्रमों तथा शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता की नियमित जांच होनी चाहिए।

14. उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के सस्थानों की मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियो के कर्ज दिलाने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।

15. ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। इसके लिए पाठ्यक्रमों में

समयानुकूल बदलाव आवश्यक है। इसके लिए प्रतिभाशाली विद्वानों, चिंतकों तथा विषय पर गहरी पकड़ रखने वालों को जोड़े रखना चाहिए। रचनात्मक और कल्पनाशील अध्यापकों को अवश्य स्थान देना चाहिए।

16. ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। विश्वविद्यालयों में विचारों की गहमा–गहमी और पारंपरिक संवाद बना रहना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। बेहतर होगा कि परंपरा और नई दृष्टि का मेल रखा जाए।

17. उच्च शिक्षा में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद सक्रिय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। मानविकी के विषयों में तर्कणा शक्ति, संवेदन, प्रेक्षण, विवेचन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

निष्कर्ष :–

इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इनमें से 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच की है। अगर इन्हें ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाए तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं। भारत देश को अगर 2020 तक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए पढ़े–लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरूरत है। हमें काफी बड़ी संख्या में इनकी जरूरत और इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तनों की जरूरत है। शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की परिकल्पना कर रहे हैं? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति और विशिष्टता के साथ उन क्षेत्रों को रेखांकित करे, जिनमें प्रामाणिक रूप से उसके द्वारा योगदान संभव है। देश की शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा के प्रति दृष्टि में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारें और शिक्षा–विशेषज्ञ अपेक्षित शैक्षणिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठायेंगे। हमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदल कर रोजगारपरक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो जिससे नवीनता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। भारत को अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी, विदेशी संस्थान तो इसमें महज सहयोग भर कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एमएचआरडी (2016). एनुअल रिपॉर्ट डिर्पाटमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन, गवरमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली..
2. एमएचआरडी (1989). नेशनल पॉलिसी आन एजुकेशन–1986, पीऑए–1990, न्यु देहलीः गवरनमेंट ऑफ इन्डिया प्रेस.
3. सिंह, आर. पी. (2010). ऑन ऑपनिंग अ 'वर्ल्ड' क्लास युनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी न्यूज, नई दिल्ली,48 (37), सितम्बर 13–19, 2010
4. सिंह, जे.डी. व अन्य, (2001). विद्यालय प्रबन्ध व शिक्षा की समस्याएं, जयपुरः रिसर्च पब्लिकेशन्स.
5. तिलक, जन्धाला (2007). हायर एजुकेशन इन इंडिया फांडिंग एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी, न्यूपा, नई दिल्ली.
6. मिश्र, अमरेश : आधुनिक शिक्षा का स्वरूप, मिश्रा बुक डिपो, इलाहाबाद, 2012।
7. वैश्य एल0पी0ःउच्च शिक्षा की दशा व दिशा, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005।
8. लिविंग्सटन रिचर्ड : शिक्षा की समस्याएँ, अनामिका पब्लिशर्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली, 2012।